भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 का सार संग्रह

भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021–22 का सार संग्रह

31 जनवरी, 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरु हुए बजट सत्र के बाद केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2021–22 पेश की। आर्थिक सर्वेक्षण देश के आर्थिक विकास का लेखा–जोखा होता है, जिसके आधार पर गत एक वर्ष की अर्थव्यवस्था का पता चलता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ अथवा नुकसान का आकलन भी प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण की एक थीम अवश्य होती है, वर्ष 2020–21 में इसकी थीम 'जीवन और आजीविका बचाना' था। आर्थिक समीक्षा 2021–22 को इस बार एक ही खण्ड में प्रस्तुत किया गया है। गत वर्षों में आर्थिक समीक्षा दो खण्डों में प्रस्तुत की जाती रही है।

वित्त मंत्री ने इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए बताया की इसका मूल विषय 'त्वरित दृष्टिकोण' है।

कोविड–19 महामारी से उबरने के पश्चात् अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों व उसके समग्र निष्पादन के साथ–साथ अर्थव्यवस्था के समक्ष स्थित विभिन्न चुनौतियों इत्यादि का लेखा जोखा इस 2021–22 की आर्थिक समीक्षा में सम्मिलित है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति–

- वर्ष 2021–22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। जबकि 2020–21 में अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022–23 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर 8–8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2021–22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 3.9 प्रतिशत, उद्योगों में 11.8 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 8.2 प्रतिशत के साथ सभी क्षेत्रों में मूल कीमतों पर जीवीए में 8.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसम्बर, 2021 तक 633.6 अरब डॉलर हो गया है।
- वित्त वर्ष 2021–22 में कुल उत्पादन वर्ष 2019–20 की तुलना में 101.9 प्रतिशत होगा।
- सकल मूल्यवर्धन (प्रचलित मूल्यों पर) में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के अन्तर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान 2020–21 के 20.2 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 18.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है (पहले अग्रिम अनुमान), उद्योगों का योगदान 25.9 प्रतिशत से बढ़कर 28.2 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 2021–22 में 53.9 प्रतिशत से घटकर 53.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

  भारत में कोविड टीकों का टीकाकरण 16 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ किया गया जिसमें–
  - पहले चरण में – 16 जनवरी से स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्त्ता एवं फ्रंटलाइन कर्मचारियों को शामिल किया गया।
  - दूसरे चरण में – 1 मार्च, 2021 से 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लिए एवं 1 अप्रैल, 2021 से 45–59 वर्ष की आयुवर्ग के लिए कोविड टीकाकरण शुरु हुआ।
  - तीसरे चरण में – 1 मई, 2021 से 18–45 वर्ष के आयुवर्ग केलिए कोविड टीकाकरण शुरू किया गया।
  - 3 जनवरी, 2022 से टीकाकरण अभियान में 15–18 वर्ष के आयु वर्ग को सम्मिलित किया गया।
  - 10 जनवरी, 2022 से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं एवं 60 वर्ष से अधिक की आयुवर्ग वाले को सह–रूग्णता सहित बूस्टर खुराक की अनुमति दी गई।
  - 16 जनवरी, 2022 तक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पहली डोज वाली आबादी (18 वर्ष और अधिक) का टीकाकरण 93 प्रतिशत एवं दूसरी डोज वाली आबादी का टीकाकरण 69.8 प्रतिशत हुआ और यह 100 प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य के साथ निरन्तर जारी है।

कोविड–19 के दौरान आपदा को रोकने के लिए गठित सुरक्षा जाल के प्रमुख उपाय

नकद हस्तांतरण लाभ	महिला जन–धन खाताधारकों को ₹500 प्रतिमाह 3 महीने के लिए जिसमें 20.64 करोड़ महिला लाभार्थियों को 30,944 करोड़ रुपये जारी किए गए।
	कमजोर वर्ग (विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग) को ₹1000 जिसमें 2.82 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए ₹2814 करोड़ जारी किए गए।
	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत (पीएम–किसान) ₹6000 प्रतिवर्ष तीन किस्तों में जिसमें फरवरी 2019 से 1 जनवरी 2022 तक 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को ₹1.8 लाख करोड़ हस्तांतरित किए गए।
खाद्य सुरक्षा	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना–80 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न के अलावा जिसे मार्च, 2020 में शुरू किया गया, चरण–V-के तहत मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया, जिसमें मार्च, 2020 से नवंबर–2021 तक, खाद्य सब्सिडी में ₹2.07 लाख करोड़ के बराबर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 600 एलएमटी खाद्यान्न आवंटित किया गया।
	वन नेशन वन राशन कार्ड पारगमन में लोगों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए पीडीएस लाभ सुनिश्चित करने के लिए जिसमें 94.3 प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आबादी को कवर करते हुए अगस्त, 2021 तक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सक्षम तथा 1.4.2020 और 30.9.2021 के बीच 24.32 करोड़ रुपये का पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए गए।

	उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर के अन्तर्गत अप्रैल से जून, 2020 के लिए 8 करोड़ लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए तथा उज्जवला 2.0 के तहत पहला रिफिल और हॉटप्लेट मुफ्त (शुरुआत 10 अगस्त 2021) सरल प्रक्रियाओं के साथ उपलब्ध कराया गया।
रोजगार लाभ	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM-GKRA) बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसरों के लिए 27 जुलाई, 21 को ₹39,293 करोड़ के व्यय के साथ 50.8 करोड़ मानव–दिवस रोजगार सृजित किए।
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 2020–21 में 389.2 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने वाले 11.2 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। ₹1,11,171 करोड़ की धनराशि जारी की तथा 2021–22 (25 नवम्बर 2021 तक) में 240.4 करोड़ कार्य दिवस पैदा करने वाले 8.85 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। ₹68,233 करोड़ की धनराशि जारी की।
	मनरेगा मजदूरी में 2019–20 की मजदूरी दर से 20 रु. की वृद्धि कर लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ–पहुंचाने के लिए मजदूरी दर 1 अप्रैल, 2020 से संशोधित की गई।
	₹15000/– से कम आय वाले 90 प्रतिशत कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत 6 महीने के लिए 12 प्रतिशत नियोक्ता और 12 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान तथा कोविड के बाद ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में संरक्षित रोजगार उपलब्ध करवाया।
	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए और उन्हें ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अन्तर्गत 20 नवम्बर, 2021 तक 1.15 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.43 लाख हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया।
आवास लाभ	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) में 2020–21 में 33.99 लाख घरों का निर्माण पूरा तथा 2021–22 (25 नवम्बर, 21 तक) में 26.20 लाख घरों का निर्माण पूरा।
	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पीएमएवाई–यू) में 2020–21 में 14.56 लाख घरों का निर्माण पूरा तथा 2021–22 में 4.49 लाख घरों का निर्माण पूरा (दिसंबर–2021 तक)।

कौशल विकास लाभ	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)–ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम डीडीयू–जीकेवाई के अन्तर्गत–डीडीयू–जीकेवाई में 2020–21 में 38,289 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 49,563 अभ्यार्थियों को नौकरी पर रखा गया तथा 2021–22 (अक्टूबर 21 तक) में 14,568 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 21,369 उम्मीदवारों को नौकरी दी गई आरएसईटीआई में 2020–21 में 207712 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 138537 अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया तथा 2021–22 (30 अक्टूबर 2021 तक) में 114640 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 61546 अभ्यार्थियों को नियुक्त किया गया।
	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत 6 राज्यों को सम्मिलित करने वाली प्रवासी कामगारों का नवीन कौशल और उच्च कौशल के अन्तर्गत 21 नवम्बर 2021 तक 1.24 लाख प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को लाभ	आरबीआई द्वारा सभी सावधि ऋणों के लिए 1.3. 2020 से 31 अगस्त 2020 तक 6 महीने का अधिस्थगन और ब्याज का आस्थगन मोहलत दी तथा 31 अगस्त 2020 तक एमएसएमई उधारकर्त्ताओं के 77.2 प्रतिशत और एससीबी के 43.7 प्रतिशत व्यक्तिगत उधारकर्त्ताओं द्वारा लाभ उठाया गया।
	एमएसएमई डिफॉल्ट ऋणों का पुनर्गठन–अगस्त, 2020 और मई 2021 आरबीआई की योजनान्तर्गत एससीबी द्वारा 12 नवम्बर 2021 तक ₹78,591 करोड़ का कुल पुनर्गठित निवेश सूची तथा पीएसबी द्वारा 9.8 लाख एमएसएमई खातों में व 58,524 करोड़ रुपये की राशि का समाधान/पुनर्गठन।
	आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना–कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए व्यवसायों (विशेष रूप से एमएसएमई) को 4.5 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी जिसमें 19 नवम्बर 2021 तक 5.45 करोड़ कर्मचारियों को प्रभावित करते हुए, 95.2 लाख उधारकर्त्ताओं को ₹2.28 लाख करोड़ वितरित किए गए तथा एमएसएमई को वितरित गारंटी राशि का 66 प्रतिशत 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया।
	एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) में क्रेडिट गारंटी/मार्जिन मनी प्रदान की गई जिसमें–2020–21 में ₹36,899 करोड़ जारी किए तथा 2021–22 में ₹22,959 करोड़ (30 नवम्बर 2021 तक) जारी किए।

	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया शुरु करने पर 1 साल के लिए रोक, और न्यूनतम सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने के लिए 25 मार्च 2020 से 24 मार्च 2021 के दौरान भुगतान में चूक माफ की गई।
	31.3.2022 तक आरबीआई द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹50,000 करोड़ की अवधि नकदी सुविधा को 31 अप्रैल 2021 को घोषित किया गया।
	सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को उधार देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के शुरुआत होने के 75 दिनों (28 जून 2021) में पूरी तरह से उपयोग तथा इसके लिए ₹7500 करोड़ स्वीकृत किए गए।
	एमएसएमई और व्यक्तियों को नए ऋण देने के लिए एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के लिए ₹45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 के अन्तर्गत 25 सितम्बर 2020 तक, ₹25,505 करोड़ के निवेश–सूची को बैंकों द्वारा अनुमोदित किया गया तथा पीएसबी: ₹27,794 करोड़ का निवेश सूची 4 दिसम्बर 2020 तक खरीदा गया।
	31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो संचालन 31 अप्रैल 2021 को घोषित किया गया।
ऋण लाभ	लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा एमएमआई को ऋण देने के लिए 31 मार्च 2022 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। इसे 31 अप्रैल 2021 को घोषित किया गया।
	नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए ₹30,000 करोड़ अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूँजी निधि के लिए 25 सितम्बर 2020 तक ₹25,000 करोड़ का वितरण तथा शेष ₹5,000 करोड़ छोटे एनबीएफसी और एनबीएफसी–एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित किया गया।
	राष्ट्रव्यापी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया जिसमें 26 नवम्बर 2021 तक ₹90,063 करोड़ ऋण स्वीकृत।
	किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान–2.5 करोड़ किसानों को ₹2 लाख करोड़ रियायती ऋण प्रोत्साहन के अन्तर्गत 1.35 लाख करोड़ की क्रेडिट सीमा के साथ 1.5 करोड से अधिक केसीसी जारी किए।
	पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरु करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 30 नवम्बर 2021 तक 30.2 लाख रेहड़ी–पटरी वालों को ₹3,054 करोड़ का ऋण जारी किया गया।
	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को संपार्श्विक मुक्त ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख जिनमें 63 लाख महिला एसएचजी, जिन्होंने 6.85 करोड़ परिवारों का समर्थन किया।
	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके गरीबी कम करने के लिए 2020–21 में एसएचजी को ₹84,143 करोड़ के ऋण वितरित किए गए तथा 2021–22 (सितंबर 2021 तक) में 21.6 लाख एसएचजी ऋण व ₹43093 करोड़ से जुडें।
	एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ की विशेष चलनिधि योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर 2020 तक, 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें ₹11.120 करोड़–₹7.227 करोड़ संवितरित शामिल थे फिलहाल यह योजना बंद कर दी गई है।
	कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹1.1 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना–स्वास्थ्य अवसंरचना, पर्यटन, आदि में दी गई जिसे 30 जून 2021 को कैबिनेट की मंजूरी, जिसमें 31 मार्च 2022 तक या ₹50,000 करोड़ स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, लागू की गई।

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 2021-22 (विभिन्न पीआईबी विज्ञप्ति, संसदीय प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक)

- केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 2021–22 के बजट अनुमान (2020–21 के अनंतिम आंकड़ों की तुलना में) 9.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की तुलना में (अप्रैल–नवम्बर 2021) 67.2 प्रतिशत तक बढ़ गई।
- राजकोषीय घाटा अप्रैल–नवंबर, 2021 के दौरान बजट अनुमान के 46.2 प्रतिशत के स्तर पर रहा।
- कोविड–19 महामारी के कारण भारत का भुगतान सन्तुलन आधिक्य में रहा जिससे 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 634 अरब डॉलर पर पहुँच गया। नवम्बर, 2021 के अंत तक भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था।

अप्रैल–नवम्बर, 2021 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में प्रमुख उत्पादों का भाग– **(प्रतिशत में)**

पेट्रोलियम	14.9
मोती व बहुमूल्य पत्थर	6.8
लोहा एवं इस्पात	6.0
औषधि फार्मूलेशन	4.7

स्वर्ण व अन्य आभूषण	2.8
ऑर्गेनिक रसायन	2.8
इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण	2.4
एल्यूमिनियम व एल्यूमिनियम उत्पाद	2.3
लोहा एवं इस्पात उत्पाद	2.0
समुद्री उत्पाद	2.0

2021–22 में अप्रैल से नवम्बर 2021 तक भारत के वस्तुगत निर्यातों के गंतव्य राष्ट्र और निर्यात– (प्रतिशत में)

अमेरिका	18.1
संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई)	6.6
चीन	5.9
बांग्लादेश	3.5
हांगकांग	2.8
सिंगापुर	2.8
नीदरलैंड	2.6
यू.के.	2.6
बेल्जियम	2.4
जर्मनी	2.3

भारत के 2021–22 में अप्रैल–नवम्बर, 2021 तक वस्तुगत आयातों में प्रमुख उत्पादों का भाग– (प्रतिशत में)

पेट्रोलियम क्रूड	19.2
स्वर्ण	8.7
पेट्रोलियम पदार्थ	6.3
पर्ल्स, प्रेशियस व सेमी प्रेशियस स्टोन	5.0
कोयला एवं कोक	4.9
इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट	3.8
वेजीटेबल ऑयल	3.2
आर्गेनिक रसायन	2.9
कम्प्यूटर हार्डवेयर	2.6
प्लास्टिक रॉ. मैटीरियल्स	2.5

भारत के 2021–22 में अप्रैल से नवम्बर, 2021 तक वस्तुगत आयातों के प्रमुख स्त्रोत देशों का भाग– (प्रतिशत में)

चीन	15.5
संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई)	7.3
अमरीका	7.2
सऊदी अरब	5.0
इराक	4.9
स्विट्जरलैंड	4.7
हांगकांग	3.2
इण्डोनेशिया	2.9
सिंगापुर	2.9
द. कोरिया	2.9

भारत का विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ सर्वाधिक अनुकूल है जबकि चीन के साथ सर्वाधिक प्रतिकूल है।

- मार्च 2021 की तुलना में दिसम्बर, 2021 में रुपए के मूल्य में 3.4 प्रतिशत का मूल्य ह्रास हुआ है।
- भारत पर कुल विदेशी ऋण सितम्बर, 2021 के अन्त में 593.1 अरब डॉलर था यह जून 2021 की तुलना में 22.3 अरब (3.9 प्रतिशत) डॉलर अधिक था।
- औसत शीर्ष सीबीआई–संयुक्त मुद्रास्फीति अप्रैल से दिसम्बर 2020–21 की 6.6 प्रतिशत की तुलना में 2021–22 में सुधरकर 5.2 प्रतिशत हुई।
- औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2021–22 में अप्रैल से दिसम्बर तक 2.9 प्रतिशत रही जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021–22 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान 12.5 प्रतिशत बढ़ी।
- 2021–22 में रेपों दर को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। सार्वजनिक निर्गमों व राइट इश्यूज के जरिए 2021–22 (नवम्बर 2021 तक) में 75 कम्पनियों द्वारा जुटाई गई कुल राशि ₹89,066 करोड़ रही यह 2020–21 में समान अवधि में 30 कम्पनियों द्वारा ₹29733 करोड़ रही थी। इसमें लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2019–20 के 60 तथा 2018–19 के 57 से 2020–21 मे सुधरकर 66 हो गया।
- भारत, विश्व में दसवाँ सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24 प्रतिशत रहे यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2 प्रतिशत।
- वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए अगस्त, 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन नियम, 2021 अधिसूचित किया गया।
- विगत दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास देखा गया। इस क्षेत्र ने देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में महत्त्वपूर्ण 18.8 प्रतिशत का योगदान 2021–22 में किया है। इसमें वर्ष 2020–21 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2021–22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- 2020–21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन होने का अनुमान है जो कि 2019–20 के दौरान प्राप्त किए गए उत्पादन की तुलना में 11.15 मिलियन टन अधिक है।
- भारत का कृषि क्षेत्र में कुल कृषि निर्यात उत्पाद 2021–22 में अप्रैल–नवम्बर (अनन्तिम) के अनुसार 31.0 अरब डॉलर रहा जो कि समान अवधि में गत वर्ष 25.2 अरब डॉलर रहा था।
- भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का उपयोग फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।
- प्रमुख उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को बढ़ावा देने से इसमें विगत वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2021–22 में पहले 6 माह (अप्रैल से सितम्बर) में एफडीआई अन्तर्वाह 42.86 अरब डॉलर तक पहुँच गया। FDI के अन्तर्गत सरकार ने स्वचलित रूट के तहत् बीमा कम्पनियों में जून 2021 में

इसकी सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की अनुमति दी तथा जुलाई, 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कुछ मामलों में स्वचालित मार्ग के तहत् 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्वचालित रूट के तहत् 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए अधिसूचना अक्टूबर 2021 में जारी की गई है।

- उद्यम पोर्टल पर 17 जनवरी, 2022 तक 66,34,006 से अधिक एमएसएमई का पंजीकरण हुआ।
- उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की शुरुआत तथा आधारभूत संरचना निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) व राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (NMP) जैसी कई पहलें की गई है इनके अतिरिक्त क्रेडिट तक आसान पहुँच के माध्यम से आपूर्ति पक्ष की बाधाओं का कम करना, एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारण्टी योजना, रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन तथा अन्य प्रत्यक्ष कर उपायों से औद्योगिक विकास में तेजी आई है।
- अप्रैल–नवम्बर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) बढ़कर 17.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गया। यह 2020–21 में समान अवधि में (–) 15.3 प्रतिशत था।
- भारतीय रेलवे के लिए पूँजीगत व्यय 2021–22 में ₹2,15,058 करोड़ तक बढ़ाने का बजट रखा गया है, इसमें 2014 के स्तर की तुलना में पाँच गुना बढ़ोतरी हुई है।
- वर्ष 2020–21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है जो 2019–20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी, इसमें 30.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है कोविड–19 महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। भारत के जीवीए में इसकी भागीदारी वर्ष 2019–20 में 55 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 53 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र में सूचना, संचार, वित्तीय, पेशेवर एवं व्यावसायिक सेवाएं लचीली बनी रही। संपर्क आधारित सेवाएँ जैसे–पर्यटन, खुदरा व्यापार, होटल, आतिथ्य तथा मनोरंजन आदि पर बहुत गंभीर प्रभाव रहा। जिससे सेवा क्षेत्र 2020–21 में 8.4 प्रतिशत संकुचित हुआ यह गिरावट उप–क्षेत्र 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवाओं में 18.2 प्रतिशत के तेज संकुचन से प्रभावित थी।
- संपर्क–गहन प्रकृति के कारण, इस उप–क्षेत्र में शामिल सेवाओं को विद्यमान महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों का सबसे अधिक आघात सहना पड़ा। सेवा उप–क्षेत्र जैसे 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं' जिसमें एक तरफ सरकार द्वारा व्यय और दूसरी ओर स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं, वर्ष में 2020–21 में 4.6 प्रतिशत वर्ष–दर–वर्ष संकुचित हुआ। अपेक्षाकृत कम संपर्क गहन उप–क्षेत्र 'वित्तीय, अचल संपत्ति तथा पेशेवर सेवाएं वर्ष 2020–21 के दौरान जीवीए में 1.5 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ सबसे कम प्रभावित हुई।
- चालू वित्त वर्ष 2021–22 की पहली छ:माही में समग्र सेवा क्षेत्र में कुल मिलाकर 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिसमें प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 8.2 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित थी। वर्ष 2021–22 की पहली छ:माही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया जो भारत में कुल एफडीआई अर्न्तप्रवाह का 54 प्रतिशत है।
- सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत पहले 10 राष्ट्रों में है, भारत के कुल सेवा निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत भागीदारी सॉफ्टवेयर निर्यात की है।
- क्रय प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) अक्टूबर, 2021 में 10 वर्षों में सबसे मजबूत छलांग लगाकर 584 हो गया तथा दिसम्बर, 2021 में पीएमआई सूचकांक 55.5 पर आ गया।
- वर्ष 2021–22 में (दिसम्बर, 2021 तक) भारतीय रेलवे द्वारा कुल माल ढुलाई 1,029.94 मिलियन टन (एमटी) थी जो वर्ष 2020–21 में इसी अवधि के दौरान 870.08 मीट्रिक टन से 18.37 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2021–22 (नवंबर, 2021 तक) में भारतीय हवाई अड्डों ने 20.97 लाख टन माल ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 14.44 लाख टन माल ढुलाई हुई थी, जिसमें 45.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष, 2021–22 में अप्रैल–नवंबर 2021 के बीच, भारतीय बंदरगाहों ने वर्ष 2020 में इसी अवधि के दौरान 779.1 मीट्रिक टन की तुलना में 857.3 मीट्रिक टन का कुल माल यातायात संभाला, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष 2021–22 में अप्रैल–नवम्बर, 2021 के दौरान भारतीय रेलवे ने 185.1 करोड़ एवं विमान सेवाओं ने 9.56 करोड़ से अधिक घरेलू यात्रियों का परिवहन किया।
- 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में सामाजिक सेवा क्षेत्र के व्यय आवंटन में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 2021–22 (बजट अनुमान) में सामाजिक सेवा क्षेत्र पर खर्च के लिए कुल ₹71.61 लाख करोड़ निर्धारित किए। पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल सरकारी व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत रहा। यह 2021–22 (बजट अनुमान) में 26.6 प्रतिशत था।
- सेवा क्षेत्र के लिए बैंक ऋण वृद्धि दिसम्बर, 2020 के अन्त में बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गई तथा यह 2021–22 में नवम्बर, 2021 तक घटकर 3.6 प्रतिशत हो गई।
- भारत में वर्ष 2020–21 के दौरान आईटी–बीपीएम सेवा राजस्व (ई–कॉमर्स को छोड़कर) 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया। यह 2.26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.38 लाख कर्मचारियों को जोड़ता है।

- भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट–अप इकोसिस्टम बन गया है। भारत में वर्ष 2021–22 में नए मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप्स की संख्या 2021–22 में बढ़कर 14 हजार से अधिक हो गई है इसमें वर्ष 2021 में 44 भारतीय स्टार्ट–अप्स ने यूनीकॉर्न दर्जा हासिल किया।
- सागरमाला कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में ₹5.53 लाख करोड़ की कुल 802 परियोजनाएं सागरमाला कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इनमें से ₹94,712 करोड़ की 181 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा ₹2.48 लाख करोड़ की 398 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- वर्तमान में, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान केवल 2 प्रतिशत है। अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्ट–अप्स की संख्या वर्ष 2019 में 11 से बढ़कर वर्ष 2021 में 47 हो गई है।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 35 रैंक हुई है, जो वर्ष 2015–16 में 81वें से वर्ष 2021 में 46 वें स्थान पर है।
- कोविड–19 के कारण बार–बार लॉकडाउन होने की स्थिति ने शिक्षा–क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित किया है।

कोविड–19 महामारी के दौरान छात्रों के लिए प्रमुख पहल

1. **पीएम ई–विद्याः** मई, 2020 में प्रारम्भ किया गया, पीएम ई–विद्या शिक्षा के लिए सुसंगत मल्टी–मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन–एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। स्कूली शिक्षा के लिए पीएम ई–विद्या के निम्न घटक हैः
(i) वन नेशन, वन डिजिटल एजुकेशन (दीक्षा) प्लेटफार्म;
(ii) स्वयं प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से वन क्लास, वन टीवी चैनल
(iii) रेडियो, सामुदायिक रेडियो एवं पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग;
2. **राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर):** शिक्षा के लिए एक डिजिटल आधारभूत संरचना, एनडीईएआर का ब्लूप्रिंट 29 जुलाई, 2021 को शुरू किया गया। इसे डिजिटल–फर्स्ट माइंडसेट के संदर्भ में स्थापित किया जाएगा जहाँ डिजिटल आर्किटेक्चर न केवल शिक्षण तथा सीखने की कार्यकलाप में सहयोग करेगा बल्कि केंद्र, राज्य तथा केंद्र–शासित प्रदेशों की शैक्षिक योजना, शासन प्रशासनिक गतिविधियों में भी सहयोग करेगा। यह डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए विविध शिक्षा इको–सिस्टम आर्किटेक्चर प्रदान करेगा, एक फेडरेटेड लेकिन इंटर–ऑपरेटेबल सिस्टम जो सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा।
3. **विद्यांजलिः** समुदाय/स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जोड़ने के लिए, सरकार ने 7 सितंबर, 2021 को 'विद्यांजलि' प्रारम्भ किया है। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय/स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान को साझा करने के लिए अपनी पसंद के स्कूलों से वार्तालाप करने और प्रत्यक्ष जुड़ने में सक्षम बनाता है तथा कौशल के साथ–साथ संपत्ति/सामग्री/उपकरण के रूप में योगदान करते हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए प्रमुख योजनाएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य देश में स्कूल तथा उच्च–शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनके निवास की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है, जिसमें कमजोर, वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकारी स्कूलों और संस्थानों में सस्ती तथा प्रतिस्पर्धी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैः

1. **समग्र शिक्षा योजना** को कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,283.04 करोड़ के साथ वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा गया है। स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के रूप में, इसमें प्री–स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह स्कूली शिक्षा को एक सातत्य के रूप में मानता है, और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी–4) के अनुसार है। यह योजना न केवल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ भी जुड़ी हुई हैः यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चों को एक–समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का ध्यान रखना तथा उन्हें पढ़ाई सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है।

इस योजना के तहत प्रस्तावित स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख भागीदारी हैः (i) सभी के लिए बुनियादी ढांचे के विकास एवं अवधारण, (ii) आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, (iii) लैंगिक समानता, (iv) समावेशी शिक्षा, (v) गुणवत्ता एवं नवाचार, (vi) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता, (vii) डिजिटल पहल, (viii) पोशाक, पाठ्यपुस्तकों सहित आरटीई पात्रताएं, (ix) बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा में सहयोग (ईसीसीई), (x) व्यावसायिक शिक्षा, (xi) खेल तथा शारीरिक शिक्षा, (xii) शिक्षक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण, (xiii) निगरानी, (xiv) कार्यक्रम प्रबंधन, और (xv) राष्ट्रीय घटक।

2. **निपुण भारत मिशनः** 5 जुलाई, 2021 को केन्द्र सरकार ने मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया, जिसे 'समझ तथा संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)' कहा जाता है। राष्ट्रीय मिशन राज्यों/केंद्र–शासित प्रदेशों के लिए प्राथमिक साक्षरता तथा वर्ग 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए संख्यात्मकता में दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वाद–योग्य कार्यसूची निर्धारित करता है। मिशन को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वधान में स्थापित किया गया है। निपुण भारत विभिन्न पहलुओं, अवधारणाओं तथा कौशल को शामिल करते हुए पढ़ाई के परिणामों एवं विकासात्मक लक्ष्यों के आधार पर बालवाटिका से शुरू होकर 9 वर्ष की आयु तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।

संजीव प्रकाशन

3. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना : इस योजना, जिसे पहले 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता था, में बालवाटिका (कक्षा एक से ठीक पहले) में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कक्षा एक से आठ में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना के तहत 11.20 लाख संस्थानों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए। केंद्र सरकार से 54061.73 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारों एवं केंद्र–शासित प्रदेशों से 31733.17 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण योजना को लागू करने के लिए अनुमोदित किया है।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत प्रमुख योजनाएं–

- ♦ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना – इसे ₹3054 करोड़ के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
- ♦ अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट – इसे प्रधानमंत्री द्वारा 29 जुलाई, 2021 को प्रारम्भ किया गया।
- ♦ ई–पाठशाला अभियान – इसे 67 विषयों में 23000 से अधिक ई–मॉड्यूल के साथ 778 पेपर विकसित किए गए है।
- ♦ उन्नत भारत अभियान – इसकी शुरुआत ग्रामीण जिलों में उच्च शिक्षा को तथा ग्रामीण स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है।
- ♦ कमजोर–वर्गों के लिए छात्रवृत्ति – इस योजना में नवम्बर, 2021–22 तक 15 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए तथा जम्मू–कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना में नवम्बर, 2021–22 तक लगभग 15000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

- कौशल विकास के अन्तर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में वर्ष 2016–17 तथा 2021–22 के बीच (15 जनवरी, 2022 तक) PMKVY 2.0 के तहत लगभग 1.10 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2021–22 में PMKVY 3.0 के तहत 3.48 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। कौशल विकास के अन्तर्गत जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) एवं शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (असीम) पोर्टल बनाया गया जो कि कुशल कार्यबल की निर्देशिका के रूप में कार्य करता है। 31 दिसम्बर, 2021 तक कौशल भारत पोर्टल (एसआईपी) तथा असीम पोर्टल पर 1.38 करोड़ उम्मीदवारों का पंजीकरण किया गया।
- लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में काम की मांग बढ़ी जिसमें जून 2020 में सर्वाधिक 6 करोड़ के स्तर पर पहुँच गयी। यह जून, 2021 में 4.59 करोड़ लोगों तक पहुँच गयी।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय 2019–20 के ₹2.73 लाख करोड़ की तुलना में 2021–22 (बजट अनुमान) में बढ़कर ₹4.72 लाख करोड़ हो गया। इसमें लगभग 73 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। शिक्षा क्षेत्र के लिए समान अवधि में यह वृद्धि 20 प्रतिशत की रही।

❑❑❑

संजीव प्रकाशन